लिए मैंने नए सिरे से पुनः योजना आयोग से अनुरोध किया है कि इस पर पुनर्विचार करके इस पर कनकरेंस दें।

MR. CHAIRMAN: Shri Solipeta Ramachandra Reddy. You put a question on Khajuraho only and nothing else.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir. there are several important tourist places like Khajuraho...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*) Dr. Raja Ramanna.

DR. RAJA RAMANNA: Sir, there are so many important artistic places which have been made pilgrimage centres. I would like to suggest that railway stations should not be located anywhere near these wonderful artistic places because people come in large numbers and spoil the whole area. But Madhya Pradesh can have any number of trains. I have got nothing to say on that matter. But I know that Sanchi is going to be spoiled. Badrinath has been spoilt. Though trains do not go there, buses go there. And the bridge across the river Ganga has spoilt the Gangotri. You make it too easy for pilgrims to go there in large numbers. They spoil the whole place. This should be borne in mind when the Minister takes a decision to put a train to a historical place like Khajuraho.

श्री नीतीश कुमारः वैज्ञानिक हैं और आणविक विस्फोट की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह सवाल उन्होंने उठाया है, उनके व्यक्तिव के दो हिस्से हैं, यह जानकार मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

श्री बालकवि बैरागीः सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं और वे उत्तर तो दे ही देंगे कि व्हाईट पेपर में वे क्या मेंशन करेंगे, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चिर कुमार प्रधान मंत्री को लेकर आप जाइए, खजुराहो के मंदिर उनको दिखाइए और वहां शिलान्यास करके आइए नई रेल लाईन का। यह आप कब कर रहे हैं, यह बताइए।

श्री नीतीश कुमारः जब तक प्रोजेक्ट का अपेक्षित मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक शिलान्यास करने में मेरा विश्वास नहीं है।

निजी तथा सरकारी उपक्रमों में उर्वरकों का उत्पादन·

*542. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः**
श्री गोविन्दराम मिरी†ः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में निजी तथा सरकारी उपक्रमों में उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में बहुत कम प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति का मूल्यांकन किया है; और यदि हां, तो उसके या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या सरकार ने संसदीय स्थायी समिति द्वारा लिये गये सुझावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है ताकि उत्पादन की स्थिति में सुधार लाया जा सके?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उर्वरक पोषकों के उत्पादन में 13.2% वृद्धि हुई।

आठवीं योजना के लिए योजना अवधि शुरू होने से पूर्व निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्यों को मुख्यतः नीति ढांचे के बारे में अनिश्चिताओं के सन्दर्भ में क्षमता निर्माण में कमी, आठवीं योजना के प्रारम्भिक वर्ष में फोस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर दिये जाने से मांग अवरूद्धता, आवर्तक फीडस्टॉक और इन्फ्रास्ट्रक्चर बाधाओं तथा रुग्ण उर्वरक उपक्रमों की कठिनाइयों के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति (एचपीसी) ने उर्वरक उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त नीति ढांचे के संबंध में सिफारिशें की हैं। एचपीसी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के संबंध में अन्तर्मंत्रालीय परामर्श तथा उद्योग के साथ बातचीत शुरू की गई है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् नई उर्वरक नीति की घोषणा की जायेगी।

(घ) उर्वरकों के उत्पादन में सुधार लाने हेतु पेट्रोलियम और रसायन संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों का सरकार ने अध्ययन किया है। स्थायी समिति की सिफारशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और बिना खाद के हम समुचित उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चौथा यूरिया उत्पादक है लेकिन खेद की बात यह है कि एक तो जहां हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, वे सिक हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और हमारा सारा ध्यान खाद को बाहर से आयात करने में लगा हुआ है। हम जिस अनुपात में और जिस कीमत पर बाहर से माल मंगा कर यहां देते है, उसको बीयर करने की क्षमता हमारे देश के किसानों में नहीं है और हालत यह है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती है और ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए उनको मिलती है और इस प्रकार खाद की कीमत बढ़ती जाती है।

श्री सभापति: अपाका सवाल क्या है? उनको बैकग्राउंड मालूम है, आप सवाल कीजिए।

श्री गोविन्दराम मिरी: महोदय, मैंने मेरे प्रश्न में यह पूछा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश में निजी और सरकारी उपक्रमों में उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में क्या बहुत कम प्रगति हुई है? उन्होंने एकदम स्वीकार तो नहीं किया है लेकिन उनके जवाब से लगता है कि कम हुई है। उन्होंने लिखा है कि the production targets set for the Eighth Plan before the commencement of the Plan period, could not be attained largely because of so many reasons.

मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: आप बताइए नहीं, सवाल पूछिए।

श्री गोविन्दराम मिरी: मैं पूछना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत उत्पादन का हमारा टारगैट कितना था? कितना उत्पादन हुआ, कितनी कमी रही? क्या इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं ताकि किसानों को सस्ती दर पर खाद मिल सके, आयात हमारा कम हो और सिक यूनिट रिवाइव हो सकें?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सभापति महोदय, हमारी कोशिश यह रही है कि देश में फर्टीलाइज़र ज्यादा पैदा हो, बाहर से कम मंगाना पड़े उस तरफ बड़ा योगदान हो रहा है, कोशिश हो रही है कि बाहर से कम से कम आए। पिछले साल में भी और इस साल भी प्रोडक्शन बढ़ी है। मैंने पांच साल के, जो पिछले फाइव ईयर प्लान के आंकड़े बताए थे कि 13.2 परसेंट उस दौरान बढ़ा। क्या कारण हुए, वह भी मैंने आंसर में डिटेल में बताया है कि पिछले साल जो टारगेट था वह 96 लाख टन नाइट्रोजन का था लेकिन हम 100 लाख टन पैदा कर सके, टारगेट से ज्यादा पैदा कर सके। ऐसे ही हमारी इस साल पिछले साल से ज्यादा पैदावार हो रही है। पिछले जो तीन महीने गुज़रे हैं—अप्रैल से जून तक—कोई 23 लाख टन उसमें नाइट्रोजन पैदा हुआ, 6.44 लाख टन फॉसफेट पैदा हुआ जब कि हमारा टारगेट इससे कम था। हमारी कोशिश यह रही है कि यहीं देश में ज्यादा पैदा हो, बाहर से कम मंगाना पड़े।

श्री गोविन्दराम मिरी: मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश के जो सात बड़े उर्वरक कारखाने हैं, हल्दिया और इस तरह के, वह कारखाने बंद हैं। 3500 करोड़ की लागत से उसको स्थापित किया गया था और एक लाख टन यूरिया के उत्पादन के बाद वह बंद हो गये हैं। सिर्फ 50 करोड़ की मांग की गयी थी, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से हम आयात कर रहे हैं। मैंने पूछा है कि उनके रिवाइवल के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? दूसरा, यह जो हनुमन्तराव कमेटी ने सिफारिश की है, उसमें एक सिफारिश यह थी कि मूल्य निर्धारण योजना बोर्ड—एक पी०पी०बी० के गठन का सुझाव दिया गया था और उसके अध्यक्ष पद पर अच्छे अर्थशास्त्री को नियुक्त करने साथ पांच सदस्यी बोर्ड बनाने की बात कही गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो सिक यूनिट के बारे में बता दें कि कब तक रिवाइव करेंगे। इस संबंध में उनकी क्या योजना है? देश को खाद के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बोर्ड का गठन हो गया है? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है और उसकी बैठकें होने के बाद क्या निष्कर्ष निकला है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: जहां तक बहुत पुरानी फैक्ट्रीज़ का ताल्लुक है, जो सिंदरी वगैरह हैं, वह बहुत देर से सिक पड़ी हैं। यह ठीक है कि हमारी कई फर्टीलाइज़र इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो बहुत देर से—हल्दिया भी उन्हीं में आ जाती है—जो बहुत देर से सिक पड़ी हुई हैं। जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि रिवाइव किया जाए किसे किया जाए, किसे न किया जाए। उनमें से अभी नामरूप का रिवाइवल का केस चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि

जल्दी नामरूप का रिवाइवल हो जाएगा। लेकिन अगर बंद पड़ी हुई हैं तो साथ के साथ नयी लगती रही हैं। जैसे पिछले साल 1997-98 में कसोल ऐक्सपैंशन हुआ, डेढ़ लाख टन यूरिया उसमें बढ़ा। फूलपुर ऐक्सपेंशन हुआ, 7.26 लाख टन यूरिया उसमें बढ़ा है, एम०एफ०एल० एक्सपैंशन हुआ, उसमें तीन लाख कॉम्पलैक्स फर्टीलाइज़र और 76 हजार टन यूरिया बढ़ा है। एन०एफ०सी०एल० का ऐक्सपैंशन हुआ। उसमें 4.95 लाख टन बढ़ा है। ऐसे ही 17.47 लाख टन पिछले साल में ही बड़ा है। इसमें कोशिश जारी है। जो पुरानी यूनिट्स हैं, उनके लिए भी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी न किसी ढंग से चलाया जाए।

श्री गोविन्दराम मिरी: आपने हल्दिया का नहीं बताया।

श्री सभापति: आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा है कि उसमें हल्दिया शामिल है।

सभा में यह प्रश्न वास्तव में श्री गोविन्दराम मिरी द्वारा पूछा गया।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, from the statement of answer it is clear that the demand of phosphatic and potassic fe tilisers had reduced or stagnated in the Eighth Plan period. It shows that the nutrients of the soil have been skewed. Sir, part (a) of my question is: Does the Government have any plan to rectify this situation? If so, what action has it taken so far and what action is it going to take in future?

Sir, part(b) of my question is this. In this Budget the Government has reduced the budgetary support for urea by Rs. 600 crores. It has been reduced from Rs. 6600 crores to Rs. 6000 crores on the assumption that the income would increase by increasing the price of urea by one rupee per kilogram. Subsequently, the Government gave up that idea. As they have given up that idea, I feel the Government is going to lose Rs. 2,000 crores on that account. By reducing the budgetary support by Rs. 600 crores, I think urea production will also be affected. I want to know whether the Government has got any plan—since they have given up that idea—so that the level of urea production is maintained.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, the prices of phosphatic fertilisers went up because in August, 1992 the price control and movement control, both were removed. As a result of that, the prices of potassic fertilisers went up. But, in the next year, in 1994-95, we had a good production of phosphatic fertilisers in the country and there was 37.3 percent increase in production of phosphatic fertilisers. So far as potassic fertilisers are concerned, we are importing it because the material is not available in the country. So, most of the time, we have to import potassic fertilisers.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I have a point. As a result of this decontrol, the nutrients of soil were skewed. They did not decontrol nitrogen fertilisers, but decontrolled phosphatic and potassic fertilisers. Due to that, there was increase in the prices of these fertilisers. The farmers were forced to buy nitrogen fertilsiers. This led to skewing of nutrients of soil. This situation has to be rectified and they should be told as to what quantity of fertilisers they should use. What are the actions taken by the Government in this regard? This is the thrust of my question.

SHRI S.S. BARNALA: Sir, the Ministry of Agriculture is taking up this matter. The farmers should be told what fertiliser should be used in what quantity. For this purpose, they have got extension programmes. The universities have extension programmes. Some of the institutes have extension programmes to inform the farmers about the proportion of fertilisrs which should be used. So far as urea is concerned, there is no dearth of it in any part of the country. We are almost becoming self-sufficient in urea production.

श्री दारा सिंह चौहान: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है जिसके कारण भविष्य में मंत्री जी को यह उत्तर न देना पड़े कि उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त कर दिए जाने से मांग

अवरूद्धता, आवर्तक फीडस्टाक और इन्फ्रास्ट्रक्चर बाधाओं के कारण कठिनाइयां पैदा न हों और फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की कमी न रहे।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर, इसमें कई बातें की जा रही हैं। जैसे—

to encourage the fertiliser industry, duty-free import of capital goods for setting up new plants and giving export benefits to indigenous supplier of capital goods of fertlisers. Similarly, there is duty-free import of fertiliser raw-material and intermediaries. Reasonable return on investment to entrepreneurs under the Retention Price Scheme Subsidy. At present, it is applicable to urea as well as other fertilisers. That is why phosphatic fertiliser production is increasing in the country. We are making all these efforts.

श्री जलालुद्दीन अंसारी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि बिहार में जो बरौनी खाद का कारखाना है वह हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के अंडर है वह अभी भी उत्पादन दे रहा है। यह कारखाना 1992 से बीआईएफआर में पड़ा हुआ और अभी भी सरकार की यह पॉलिसी है कि ऐसी जो फर्टिलाइजर कम्पनियां हैं, जिनका रिवाइवल किया जा सकता है, जिनकी वायबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, उसको रिवाइवल पैकेज में लाया जाए। जब वह बन्द हो जाएगा तब रिवाइवल पैकेज लाने के क्या मायने होंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में बरौनी फर्टिलाइजर कम्पनी को रिवाइवल पैकेज में लाने के लिए, बीआईएफआर से उसको मुक्त करके, वहां फिर से उत्पान शुरू हो, इसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

†شری جلال الدین انصاری: ادھیکش مہودے، میں منتری جی سے آپکے مادھیم سے یہ جاننا چاہونگا کہ بہار میں جو بیرونی کھاد کا کارخانہ ہے وہ ہندوستان فرٹیلائزر کارپوریشن کے اندر ہے وہ ابھی بھی اتپادن دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ ۱۹۹۲ء سے بی۔آئی۔ایف۔آر میں پڑا ہوا ہے اور ابھی بھی سرکار کی یہ پالیسی ہے کہ ایسی جو فرٹیلائزر کمپنیاں ہیں، جن کا ریوائیول کیا جا سکتا ہے، جنکی وائبلٹی ہے، فزیبلٹی ہے، اسکو ریوائیول پیکیج میں لایا جائے۔ جب وہ بند ہو جائیگا تب ریوائیول پیکیج لانے کے کیا معنی ہونگے؟ میں مانیہ منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سمبندھ میں بیرونی فرٹیلائزر کمپنی کو ریوائیول پیکیج میں لانے کے لئے بی۔آئی۔ایف۔آر۔ سے اسکو مکت کرکے وہاں پھر سے اتپادن شروع ہو، اسکے لئے کون سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟

†[ ]Transilteration in Arabic Script

श्री जनार्दन यादव: सर, बिहार में सिन्दरी खाद का कारखाना भी है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर, बरौनी खाद का कारखाना 1992 से ही बीआईएफआर के पास है और सिक इंडस्ट्री हो गई है इसलिए वहां पड़ी हुई है और जो प्रोडेक्शन बता रहे हैं वह तो नाममात्र का प्रोडेक्शन है। यह सिक यूनिट है और ऐसा लग रहा है कि शायद इसका रिवाइवल न हो सके। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि जो रिवाइव हो सकते हैं उनको रिवाइव किया जायेगा।

श्री जनार्दन यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में दो खाद के कारखाने हैं सिन्दरी और बरौनी। सिन्दरी पहले ही बन्द हो चुका है और बरौनी बन्द होने को है। क्या मंत्री जी सिन्दरी कारखाने को पुनः चालू करने के लिए किसी पैकेज में उनका नाम आया है या नहीं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सिन्दरी का नाम सिक यूनिट्स की लिस्ट में चल रहा है। इसको रिवाइव करने पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सभापति महोदय, उत्तर जानने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी यही उत्तर मिलेगा। फिर भी मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि दुर्गापुर सार कारखाने के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल में एकमात्र यूरिया उत्पादन करने वाली संस्था है। दस लाख टन यूरिया हमें यहां से मिल सकता है। केवल 40 करोड़ के अभाव में यह जनवरी 97 से बंद पड़ी है। इसके लिए क्या आप आश्वासन देंगे? अभी आपने उत्तर दिया कि बाहर से कम से कम यूरिया आये, इसकी कोशिश करेंगे और 100 लाख टन यूरिया पैदा कर सकेंगे। वहां दस लाख यूरिया की खपत हमारे पश्चिमी बंगाल में है। उसको एक हद तक पूरा करने वाली इस संस्था के रिवाइवल के लिए आप क्या कोई आश्वासन देंगे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: यह भी उसी लिस्ट में आती है। आप जो 40 करोड़ की बात कर रहे हैं यह और ऑनरेबल मेम्बर्स ने भी बताई है। हम इसके भी देख रहे हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: उनका जवाब तो सुन लीजिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: 40 करोड़ खर्च करने पर ये चल भी सकेंगे, चलते रहेंगे कुछ फायदा भी देंगे या फिर घाटे में चले जाएंगे, इसके कई आस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है।

Upgradation of Rail Track

*543. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to State:

(a) whether the Railways are thinking of rail track upgradation so that the speed of selected trains could be increased beyond the present limit of 130 kmph;

(b) if so, whether the Railways have matching infrastructure to avoid any mishaps or to take care after major mishaps happen due to high speed trains; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर, रेल मंत्री जी ने तो हमारे सवाल को बिल्कुल उड़ा ही दिया है, समझ में नहीं आया। अच्छा होता, रेल मंत्री जी उस जवाब को पढ़ लेते जो जवाब लोक सभा में राम नाईक जी ने दिया था सवाल के जवाब में।

श्री संघ प्रिय गौतम: ...(व्यवधान)... नहीं दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: अगर आप मुझे प्रश्न करने दें तो आपकी कृपा होगी।

जो उत्तर दिया गया है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं:

> "In view of the fact that the speed of the trains in the country is much lower compared to those of other countries, measures are underway to remove speed restrictions and upgrade tracks." It was said in the Lok Sabha on Thursday that the Railway Board has limited the maximum speed of trains of the Indian Railways to 120 to 130 kms. per hour. The Minister of State for Railways, Mr. Ram Naik stated it in his written reply.

राम नाईक जी ने अपने लिखित उत्तर में यह बात कही है कि वे विचार कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। आखिर, यह मंत्री जी जानें। लेकिन मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कठिनाई कहां है। सभापति जी, यह रेलवे स्थायी समिति की एक रपट है। इसमें कहा गया है, मैं पढ़ना चाहूंगा कि:

> "चूंकि रेल यातायात गाड़ियों की गति और उनके भार में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है, अतः गाड़ियों का संचालन कार्य अधिक जटिल होता जा रहा है और इसमें मानवीय त्रुटियों की अधिक संभावना है। इसके परिणामस्वरूप असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और इसके कारण दुर्घटनायें बढ़ रही हैं"। यह रेल मंत्रालय की स्थायी समिति ने कहा है।

श्री सभापति: सवाल कीजिए।